February 7, 2024

[सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला कलेक्टरों और सीईओ, जिला परिषद के साथ बैठक की।]

7 फरवरी, 2024 को सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला कलेक्टरों और सीईओ, जिला परिषद के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के 70 जिला कलेक्टर/सीईओ जिला परिषद/ जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन आईसी और जीडब्ल्यू), जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, राज्यों और एनपीएमयू, अटल भूजल योजना के उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के प्रारम्भ में, सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने कार्यक्रम की भावना पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पायलट कार्यक्रम है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डिमांड-साइड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने स्मार्ट कृषि और सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवाचार को शामिल करने के महत्व और बड़े पैमाने पर प्रतिकृति के लिए अंतर-राज्यीय पीयर-टू-पीयर लर्निंग पर जोर देते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के मेहसाणा, सिरसा, रामनगर, निवाड़ी, नागपुर, राजसमंद और शामली जिला के कलेक्टरों// अथवा सीईओ, जिला परिषद ने अपने जिलों में अटल जल के कार्यान्वयन और, भूजल प्रबंधन के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया।